नोबेल ने हमें जो सपने दिए

इस बार के नोबेल शांति पुरस्कार ने दुनिया को यह मौका दिया है कि वह बाल मजदूरी के क्रूर सच का सामना करे।

स्वामी अग्निवेश
सामाजिक कार्यकर्ता

मैंने 1979 के नवंबर में हरियाणा के शिक्षा-मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और यह तय किया कि हम बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी जैसे सामाजिक मुद्दों को उठाएंगे, ताकि इनका जड़ से उन्मूलन हो सके। 1980 के शुरू में हम हरियाणा के सटे फरीदाबाद में पत्थर खदान मजदूरों के पास सीधे पहुंचे और उनके बीच हमारा सामाजिक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। तब जो बातें हम सुन रहे थे, उनसे सीधा साबका हमारा पड़ा कि वहां गुलामों की तरह मजदूर खरीदे-बेचे जा रहे हैं। यह हम सबके लिए एक बड़ा झटका था कि तमाम बड़े लोकतांत्रिक और न्यायिक प्रतिष्ठानों की नाक के नीचे यह अवैध काम धड़ल्ले से जारी है। इस तरह, साल 1981 में हमारा बंधुआ मुक्ति मोर्चा बना और इसके एक-डेढ़ साल के अंदर कैलाश सत्यार्थी जी हमारे साथ जुड़े। हम दोनों ने समवेत स्वर में बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी को उठाया। लेकिन एक घटना जिसने इस मुहिम को राष्ट्रीय रंग प्रदान की और आज इस अंतरराष्ट्रीय मुकाम तक लाई है, वह थी मिर्जापुर में बाल मजदूरी की। यहां के कालीन उद्योग में तब बिहार से लाए गए बच्चे काम करते थे। उनका बचपन तो इससे छीन ही रहा था, बल्कि मानवाधिकार हनन की हद तक उनसे काम लिया जा रहा था। जब हम दोनों को यह मालूम हुआ, तो एक व्यापक सामाजिक अभियान की हमने शुरुआत की। फलस्वरूप, 32 बाल मजदूरों में से 28 बच्चों को हम छुड़ाने में सफल रहे। इस घटना से मैं समझता हूं कि पहली बार लोगों को पता चला कि देश में सिसकते बच्चों की क्या स्थिति है और उनके साथ निर्ममता की किस हद तक अत्याचार हो रहे हैं। मानवता को आईना दिखाने का काम हमने किया था।

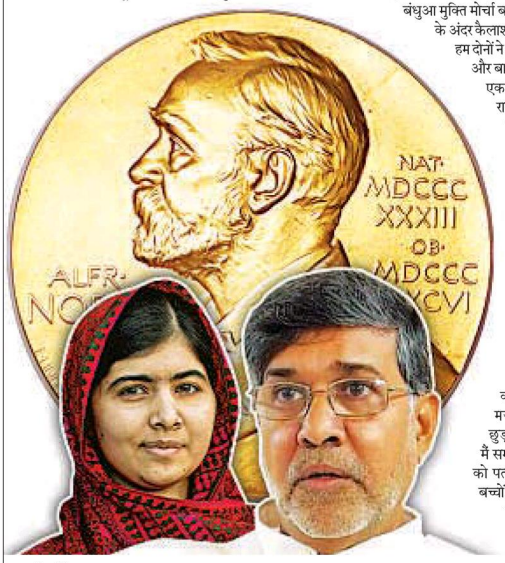

डी. श्रीनिवास

जब आज हमारे कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की बच्ची मलाला यूसुफजई को 'बाल-शोषण और नौजवानों के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष तथा सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार' के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए साल 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई, तब मुझे अंतर्मन से बेहद खुशी हुई कि इस गंभीर सामाजिक मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाना गया है। इस विकराल समस्या को पहचानने और उसके उन्मूलन की जरूरत इस दुनिया को न जाने कब से है।

अकेले हमारे भारत में कोई पांच करोड़ बच्चे बाल मजदूरी, बाल तस्करी, शोषण और अन्य सामाजिक बुराइयों से त्रस्त हैं। यह संख्या वही है, जो हम आप-सुनते आ रहे हैं, या जो कहीं आंकड़ों के रूप में उपलब्ध हैं, सच्चाई इससे भी कड़वी हो सकती है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान बांग्लादेश और नेपाल में स्थिति और बुरी हो सकती है। पाकिस्तान तंगहाली के अलावा अपने ही आतंकवाद का शिकार देश बन चुका है और बांग्लादेश व नेपाल में काफी गरीबी है ही। अफगानिस्तान की आर्थिक और सामाजिक हालत पर अभी कोई टिप्पणी बेमानी ही होगी। इस तरह जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें बच्चों की स्थिति अच्छी तो नहीं ही है। हम एक ऐसा समाज बनाते और बुनते जा रहे हैं, जिसमें बच्चे 'टेकन फॉर ग्रांटेड' हैं और जब गरीबी एक बड़ी क्षेत्रीय समस्या हो, तब गरीब परिवार के बच्चों की दयनीय हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अक्सर यह देखने को मिलता है कि हमारे अनुमान से भी अधिक ये शोषण के शिकार हैं। इसी तरह, दुनिया के स्तर पर, जहां एशिया महादेश के अलावा अफ्रीका जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं, वहां बाल मजदूरी भयावह सपनों जैसी ही हो जाती है। ऐसे में, मानव सभ्यता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, इस धरती पर बचपन बचाने की। विकास की अंधी दौड़ में हम इस चुनौती से मुकाबिल होने के रास्ते से दूर जा रहे थे। लेकिन दुनिया का शीर्षस्थ सम्मान ने इस तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है और इसके लिए हमें सचमुच नोबेल अकादमी का शुक्रगुजार होना चाहिए। जाहिर है, यह हम सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है कि दुनिया के उन तमाम सिसकते बच्चों की आवाज 'नोबेल पीस प्राइज' समिति ने सुनी।

जिन दो नामों को यह पुरस्कार देने की घोषणा हुई, चाहे वह बचपन बचाओ आंदोलन के कैलाश सत्यार्थी हों या फिर पाकिस्तान में तालिबानी आतंकवाद का मुकाबला करने वाली और लड़कियों की शिक्षा की लड़ाई लड़ने वाली मलाला यूसुफजई हों, उन्होंने हाशिये पर पल-बढ़ रहे बच्चों के जीवन को संवारने का भरोसा पैदा किया है और इनके लिए आगे बढ़कर काम करने का संकेत भी किया है। इस पुरस्कार के बहाने दुनिया को यह मौका मिला है कि वह उन बच्चों के क्रूर सच का सामना करे और उनके लिए बेहतर भविष्य का रास्ता बनाए। लेकिन यह काम आसान नहीं है। गुलामी की मानसिकता को खत्म किए बगैर यह काम संभव नहीं है। यह सबके लिए समान अवसर और सामाजिक बराबरी के बिना मुमकिन नहीं। खास तौर पर भारत के मामले में सभी तबकों के बच्चों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था जरूरी है। असमान शिक्षा और अवसर की असमानता हमारे इन उपेक्षित बच्चों के लिए दो बड़े संकट हैं।

शिक्षा का अधिकार कानून जब बना था, तब उससे बड़ी उम्मीद बंधी थी। लेकिन विडंबना देखिए कि अभी तक कई जगहों पर इस कानून पर समूचे रूप में अमल नहीं हो पा रहा है। एक देश कैसे विकास के आसमान पर पहुंचेगा, जब उसके लाखों- करोड़ों बच्चों, गरीब परिवार के मासूमों को शिक्षा के बुनियादी हक से वंचित किया जा रहा हो? महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ *सत्यार्थ प्रकाश* में कहा है- चाहे राजा का पुत्र हो या फिर प्रजा का, सबको विद्यालय में एक समान खान-पान और एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे देश के नए और सुनहरे भविष्य के लिए यह आवश्यक है। इस बार के नोबेल शांति पुरस्कार ने जो हमें सपने दिए हैं, आइए उनको हम हर बच्चे की आंखों में भरें।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

Ads by OffersWizard

Ad Options